राज्य योजना 2016–17 की प्रगति की समीक्षा

14 जुलाई, 2016

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य का स्वीकृत उद्व्यय– ` 71501.84 करोड़
- अतिरिक्त उद्व्यय के साथ कुल उद्व्यय– ` 78040.47 करोड
- दिनांक 13.07.2016 तक व्यय– ` 7388.52 करोड़
- व्यय का प्रतिशत
  - मूल उद्व्यय का– 10.33 प्रतिशत
  - अतिरिक्त उद्व्यय के साथ कुल उद्व्यय– 9.47 प्रतिशत

- गत् वर्ष 2015–16 का उद्व्यय– ` 57137.62 करोड़
- गत् वर्ष 2015–16 में इस अवधि तक का व्यय– ` 8804.24 करोड़ (15.41 प्रतिशत)

निम्नांकित 9 विभागों का व्यय 9.47 (राज्य औसत) प्रतिशत से अधिक :–

¼:0 yk[k e½

क्र0	विभाग का नाम	अतिरिक्त उद्व्यय के साथ कुल उद्व्यय	वर्तमान माह (%)	गत माह (%)
1	सूचना प्रावैधिकी	32247.89	46.75	42.76
2	गन्ना विभाग	10184.27	41.22	0.00
3	वाणिज्य कर विभाग	603.77	33.00	0.00
4	पथ निर्माण विभाग	565141.00	30.52	13.72
5	जल संसाधन विभाग	141543.13	27.60	27.44
6	ऊर्जा विभाग	965860.00	19.95	15.17
7	ग्रामीण कार्य विभाग	595431.00	17.75	7.65
8	आपदा प्रबंधन विभाग	5039.00	10.54	7.14
9	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	133567.00	9.75	5.66

निम्नांकित 11 विभागों की स्वीकृति 40 प्रतिशत से कम है :–

¼:0 yk[k e½

क्र0	विभाग का नाम	स्वीकृत उद्व्यय	कुल स्वीकृत राशि	स्वीकृति का प्रतिशत
1	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	157598.84	61584.74	39.08
2	पंचायती राज विभाग	163992.00	61100.00	37.26
3	सहकारिता विभाग	49670.19	16141.88	32.50
4	ग्रामीण विकास विभाग	862305.69	243488.78	28.24
5	श्रम संसाधन विभाग	78094.38	20844.73	26.69
6	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	212163.36	40745.26	19.20
7	स्वास्थ्य विभाग	535692.00	62216.38	11.61
8	विधि विभाग	29667.00	2707.00	9.12
9	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	22771.14	370.00	1.62
10	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	158549.66	499.06	0.31
11	परिवहन विभाग	1487.17	0.00	0.00

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत भारत सरकार से विमुक्त राशि

- मूल उद्व्यय/बजट उपबंध– `28777.82 करोड़
- 30, जून 2016 तक भारत सरकार से विमुक्त राशि– `4013.15 करोड़
- विमुक्त राशि का प्रतिशत– 13.95 प्रतिशत
- 30 जून, 2016 तक कुल व्यय– `1819.04 करोड़
- विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत– 45.33 प्रतिशत

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 30 योजनाओं के विरूद्ध केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त है (जून, 2016):–

(रू0 करोड़ में)

क्र0	विभाग का नाम	योजना का नाम	उद्व्यय/ बजट	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षा विभाग	एम0डी0एम0	1005.00	614.63	0.00
2	शिक्षा विभाग	सर्व शिक्षा अभियान	4466.03	593.73	593.73
3	ग्रामीण कार्य विभाग	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3000.00	574.80	574.80
4	समाज कल्याण	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	1497.49	568.96	0.00
5	समाज कल्याण	आई0सी0डी0एस0	1810.81	332.64	1.89
6	ग्रामीण विकास विभाग	इंदिरा आवास योजना	1413.33	329.45	0.00
7	ग्रामीण विकास	मनरेगा	1859.42	235.00	0.00
8	नगर विकास एवं आवास विभाग	सरदार पटेल शहरी आवास योजना	157.21	174.18	0.00
9	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)	350.00	94.77	74.60

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 30 योजनाओं के विरूद्ध केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त है (जून, 2016):–

(रू0 करोड़ में)

क0	विभाग का नाम	योजना का नाम	उद्व्यय/ बजट	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6
10	ग्रामीण विकास	एन0आर0एल0एम0	519.89	81.83	0.00
11	नगर विकास एवं आवास	स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)	80.00	81.73	0.00
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	निर्मल भारत अभियान/स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)	345.00	65.93	0.00
13	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	72.72	53.97	0.00
14	पथ निर्माण विभाग	केन्द्रीय सड़क निधि	0.00	37.02	0.00
15	योजना एवं विकास विभाग	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	69.75	30.85	0.00
16	कृषि विभाग	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	60.00	21.60	0.00
17	स्वास्थ्य विभाग	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	0.00	20.00	0.00

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 30 योजनाओं के विरूद्ध केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त है (जून, 2016):–

(रू0 करोड़ में)

क0	विभाग का नाम	योजना का नाम	उद्व्यय/ बजट	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6
18	स्वास्थ्य विभाग	राष्ट्रीय आयुष मिशन	24.45	17.53	0.00
19	कृषि विभाग	कृषि प्रसार मिशन	62.13	15.37	0.00
20	कृषि विभाग	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	30.00	11.96	0.00
21	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	सहायक अनुदान	0.00	9.00	0.00
22	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण विभाग	प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति	10.29	8.50	0.00
23	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	अनु0 जाति के विकास के लिए योजना	119.35	8.31	4.04
24	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	अल्पसंख्यकों का बहुप्रक्षेत्रक विकास	145.44	7.66	6.89
25	शिक्षा विभाग	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	80.00	7.12	0.00

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 30 योजनाओं के विरूद्ध केन्द्र सरकार से राशि विमुक्त है (जून, 2016):–

(रू0 करोड़ में)

क0	विभाग का नाम	योजना का नाम	उद्व्यय/ बजट	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6
26	शिक्षा विभाग	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	80.00	6.60	0.00
27	समाज कल्याण	आई0सी0पी0एस0	15.00	5.52	0.00
28	अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग	अनु0 जनजाति उप योजना (टि0एस0पी0)	0.00	3.00	0.00
29	नगर विकास एवं आवास विभाग	शहरी गरीबी उन्नमूलन (पूर्व का दायित्व)	0.00	1.40	0.00
30	श्रम संसाधन विभाग	नेशनल कैरियर सर्विसेज (CASP)	0.00	0.09	0.00
	कुल		**17273.31**	**4013.15**	**1255.96**

वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत 5 योजनाओं के विरूद्ध केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि शून्य है लेकिन व्यय हुआ है:–

(रू0 करोड़ में)

क0	विभाग का नाम	योजना का नाम	उद्व्यय/ बजट	विमुक्त राशि	व्यय
1	2	3	4	5	6
1	ऊर्जा/पथ निर्माण	बी0आर0जी0एफ0	6395.19	0.00	474.25
2	जल संसाधन/लघु जल संसाधन	ए0आई0बी0पी0	355.11	0.00	59.15
3	पथ निर्माण	सड़क एवं पुल	170.00	0.00	28.25
4	विधि विभाग	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायालयों के लिये आधारभूत सूविधा का विकास	70.00	0.00	1.16
5	जल संसाधन	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	48.57	0.00	0.27
	कुल		**6938.87**	**0.00**	**563.08**

महत्वपूर्ण मुद्दे:–

➢ <u>सत्त विकास लक्ष्य (SDG)</u>

• सतत विकास लक्ष्य (SDG) के तहत 15 वर्षों का Vision Documents, वर्ष 2017–18 से वर्ष 2023–24 के लिए 7 वर्षों की रणनीति एवं 3 वर्षों यथा 2017–18 से 2019–20 का कार्य योजना सभी संबंधित विभागों से अप्राप्त।

• दिनांक 13.05.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से संबंधित बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ड्राफ्ट मैपिंग संबंधी प्रतिवेदन ग्रामीण कार्य, समाज कल्याण, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सामान्य प्रशासन विभाग को छोड़कर शेष विभागों से अप्राप्त ।

दिनांक 09.06.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:–

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को 30 जून 2016 तक योजनाओं को निश्चित रूप से पारित करा लेने का निदेश। अन्यथा विभागों के पास अवशेष उद्व्यय को काटकर सात निश्चय से संबंधित विभागों को उनकी मांग के आधार पर उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा सकती है।	सभी विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।
मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को पूर्व में स्वीकृत योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करा लेने का निदेश। निधि के बचने पर ही नई योजनाओं को स्वीकृत करने का निदेश।	सभी विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।

दिनांक 09.06.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:–

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि क्षेत्र भ्रमण के क्रम में प्रायः पाया जाता है कि योजना पूर्ण है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्माण एजेंसी/विभाग द्वारा योजना पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित विभाग को लिखित सूचना देने का निदेश। इसी को हस्तांतरण मान लिया जायेगा।	सभी संबंधित विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।
मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों को योजनाओं की स्वीकृति की साथ शिलान्यास एवं पूर्णता की तिथि/संभावित उद्घाटन की तिथि तय करने का निदेश।	सभी संबंधित विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।

दिनांक 09.06.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:–

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत 31 मई 2016 तक भारत सरकार से बजट उपबंध `28777.82 करोड़ के विरूद्ध मात्र 16 योजनाओं में कुल `2347.87 करोड़ विमुक्त। मुख्य सचिव द्वारा संबंधित विभागों को अपने स्तर से संबंधित मंत्रालयों में वांछित प्रतिवेदन भेजते हुए राशि विमुक्ति हेतु प्रयास करने का निदेश।	सभी संबंधित विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।
मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि विभागों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर केन्द्र सरकार को अगली किस्त की विमुक्ति के प्रस्ताव के साथ इन्हें भेजा जाता है। उनके द्वारा CTMIS के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए विचार करने हेतु वित्त विभाग को सुझाव।	वित्त विभाग से कार्रवाई अपेक्षित।

दिनांक 09.06.2016 को संपन्न राज्य योजना की समीक्षात्मक बैठक में विभागवार प्राप्त निदेश जिनपर संबंधित विभागों से कार्रवाई/अनुपालन अपेक्षित है:–

प्राप्त निदेश	की गयी कार्रवाई
प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को मिलने वाले विशेष पैकेज का राज्य द्वारा क्रियान्वयन के अनुश्रवण हेतु माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निकट भविष्य में पैकेजवार/योजनावार समीक्षा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव एवं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के संबंधित पदाधिकारियों के साथ की जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा सभी संबंधित विभागों को उक्त समिति द्वारा वांछित प्रश्नावली में उल्लेखित बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश।	सभी संबंधित विभागों से कार्रवाई अपेक्षित।
मुख्य सचिव द्वारा सभी संबंधित विभागों को सतत् विकास लक्ष्य (SDG) से संबंधित प्रतिवेदन योजना एवं विकास विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश।	ग्रामीण कार्य, समाज कल्याण, कृषि, सूचना प्रौद्यौगिकी एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त। शेष अन्य विभागों से अप्राप्त।

धन्यवाद